भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5192
उत्तर देने की तारीख-03/04/2023

राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय

†5192. श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) :
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्रीमती नवनित रवि राणा:
श्रीमती लॉकेट चटर्जी:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक :
श्री देवजी पटेल:
श्री अजय कुमार मंडल:
श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय के उद्देश्य क्या हैं और संपूर्ण देश में इससे लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है तथा उक्त विश्वविद्यालय के लिए कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि देश में अभी भी वंचित लोगों तक इंटरनेट की पहुंच नहीं है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे अधिक से अधिक लोगों के लिए उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में कमजोर समुदायों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क डिजिटल उपकरण प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) छात्रों की डिजिटल साक्षरता की कमी और डिजिटल उपकरणों तक उनकी सीमित पहुंच जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं/ किए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क): भारत सरकार ने अपनी बजट घोषणा 2022-23 में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। इससे देश भर के छात्रों को अपने-अपने घरों पर ही शिक्षा के निजीकृत अनुभव के साथ विश्व स्तरीय गुणवत्ता युक्त सर्वसुलभ शिक्षा तक पहुंच प्राप्त होगी। डिजिटल विश्वविद्यालय की मुख्य विशेषता, आईआईटी-

मद्रास, दिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईटी-दिल्ली, आईआईटी-खड़गपुर,आदि जैसे विभिन्न शीर्ष संस्थानों की साझेदारी से तैयार हब बिल्डिंग अत्याधुनिक आईसीटी विशेषज्ञता वाला एक नेटवर्क हब-स्पोक मॉडल है। 2023 में डिजिटल विश्वविद्यालय के संचालन के लिए प्रमुख सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) आदि जैसे वैधानिक नियामक निकायों से शिक्षा, प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में निजी और सरकारी विशेषज्ञों के साथ अनेक हितधारक परामर्श बैठकें आयोजित की जा रहीं हैं।

डिजिटल विश्वविद्यालय के लिए हब एंड स्पोक मॉडल को लागू करने के लिए 01 फरवरी 2022 को वर्ष 2025-26 तक अनुमोदित एनएमईआईसीटी चरण-III योजना का लाभ उठाया जा रहा है। एनएमईआईसीटी को 2022-23 के लिए 400 करोड़ रुपये का वार्षिक आवंटन किया गया था और अब तक 395 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

(ख) और (ग) अपवंचित वर्गों सहित सभी छात्रों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने हेतु कई पहल की जा रही हैं। अपवंचित लोगों सहित सभी के लिए शैक्षिक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, बहु-भाषी सामग्री, सुलभ शिक्षण प्रबंधन प्रणाली, मजबूत शिक्षा समुदाय तैयार करने के लिए सहपाठी शिक्षार्थियों को जोड़ने और स्वयम, प्रभा टीवी चैनल आदि के माध्यम से मल्टी-मोडल शिक्षा का मिश्रण करके समकालीन, अनुभवात्मक शिक्षा जैसी विभिन्न पहलों की योजना बनाई गई है। उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करने के लिए अनेक उच्च शिक्षण संस्थानों को 1 जीबीपीएस एनकेएन (नेशनल नॉलेज नेटवर्क) कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है।

(घ) से (च) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) -2020 में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रम के लिए अनिवार्य है और सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में शैक्षिक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने की आवश्यकता को चिन्हाकित किया गया है ताकि इसे सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों सहित विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ बनाया जा सके। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे छात्रों और शिक्षकों की मांगों को पूरा करने के लिए प्रत्येक स्थान पर मौजूद स्थिति के आधार पर कार्य करें ताकि उन्हें डिजिटल रूप से सीखने के लिए अपेक्षित डिजिटल पहुंच प्रदान की जा सके। समग्र शिक्षा के आईसीटी और डिजिटल पहल घटक के रूप में छठी से बारहवीं कक्षा वाले सरकारी स्कूलों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास रूम्स स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान के घटकों के तहत निधि प्रदान की जाती है, जिसका उपयोग लाभार्थी संस्थानों द्वारा आईसीटी सुविधाओं में सुधार सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

*****